गैर-हिन्दी राज्यों में हिन्दी की प्रोन्नति के लिए कार्यक्रम

1567. **श्री कपिल वर्मा :**

श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दी की प्रोन्नति, प्रचार और प्रयोग के लिए सरकार ने कितने कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-हिन्दी भाषी/राज्यों में हिन्दी की प्रोन्नति को बढ़ावा देने के लिए मुख्यतः निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम लागू करता रहा है :—

1. गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हिन्दी शिक्षकों का नियुक्ति तथा साथ ही साथ हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता ।

2. हिन्दी की प्रोन्नति तथा प्रचार के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता (अनुमोदित खर्च संबंधी अनुमानों के 75 प्रतिशत की दर से सहायता प्रदान की जाती है)

3. हिन्दी में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायता (अनुमोदित खर्च संबंधी अनुमानों के 80 प्रतिशत की दर से)

4. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन द्वारा गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण ।

5. संगठनों (संस्थाओं/पुस्तकालयों) को निःशुल्क वितरित करने के लिए हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों का क्रय ।

6. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक अधीनस्थ अनुष्ठान द्वारा हिन्दी शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम ।

7. के० हि० नि० द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में द्विभाषी व बहुभाषी शब्दकोष तैयार करना ।

8. शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय-वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में शब्दकोश का (ग्लोसरी) संकलन तथा उन्हें तैयार करना ।

9. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा विश्वविद्यालय/कालेज स्तर के शिक्षकों को हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं की ओर अभिमुख करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन ।

10. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा गैर-हिन्दी लेखकों को हिन्दी में पुस्तकें लिखने के लिए पुरस्कार प्रदान करना ।

11. स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न हिन्दी परीक्षाओं को मान्यता प्रदान करना ।

12. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत गैर हिन्दी भाषी राज्यों के स्कूलों में द्वितीय/तृतीय भाषा के रूप में हिन्दी का शिक्षण ।

13 गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को दसवीं के बाद हिन्दी में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति ।

Bringing the Societies deemed at State under the Jurisdiction of Central Administrative tribunals

1568. SHRI RAM AWADHESH SINGH:

SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any provision for bringing Societies deemed as State under

Article 12 of the Constitution, within the Jurisdiction of Central Administrative Tribunals; and

(b) if so, the details thereof?

THE PRIME MINISTER AND MINISTER OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) and (b) Although under Section 14(2) of the Administrative Tribunals Act, 1985 there exists a provision for bringing all Corporations/Societies and local and other authorities owned and controlled by the Govt. of India, under the purview of the Central Administrative Tribunal, no such general notification covering all such corporations/societies including public sector undertakings has so far been issued as the CAT is not presently in a position to take up additional work involved in respect of Public Sector Undertakings, etc. However, a list of organisations|societies which have so far been brought under the purview of CAT is annexed.

Statement

S. No.	Name of the Corporation/Society/Other authority	Status
1.	Central Board of Trustees Constituted under the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1972.	Statutory body.
2.	Employees' State Insurance Corporation . .	Corporation.
3.	Central Board for Workers' Education . .	Registered Society.
4.	National Labour Institute	Registered Society.
5.	National Council of Safety in Mines, Dhanbad .	Registered Society.
6.	Council for Scientific and Industrial Research .	Registered Society.
7.	Central Social Welfare Board	An authority controlled by the Government.
8.	Indian Council of Agricultural Research . .	A society controlled by the Government.

Controversy over Industrial Dearness Allowance to Public Sector undertakings

1569. SHRI KRISHAN LAL SHARMA:

SHRI V. NARAYANASAMY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the industrial dearness allowance for Public Sector Undertaking is creating a major controversy as the officers of the Central Public Sector Undertakings proposed a strike recently and are demanding dearness allowance either on the Central Government pattern or on the pattern of banking sector, if so, Government's response thereto;

(b) whether Government have held negotiations with the officers of the Association to resolve the dispute; and

(c) if so, what has been the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BHAGEY GOBARDHAN): (a) to (c) The Executives of the Central Public Sector Enterprises who are on the Industrial DA pattern are demanding Dearness Allowance on the pattern of Central Government or the Banking Sector. During the discussions with Government, it was explained that the DA formula has to be viewed as part o